



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 8 सितम्बर, 1993/17 भाद्रपद, 1915

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 सितम्बर, 1993

संख्या ई० ए० १० ए० १० ए० १० (11) 2/93.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश टैक्स ग्रान एन्टी आफ गुड्स इन टू लोकल एरिया ऐक्ट, 1985 (1985 का 11) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची-1 के स्तम्भ (2) में क्रम संख्या 6 व 7 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर स्तम्भ-8 में विनिर्दिष्ट विद्यमान प्रवेश कर की दरों को "3 प्रतिशत" से "4.5 प्रतिशत" करने के संशोधन का प्रस्ताव करते हैं। कोई हितवद्ध व्यक्ति जिसका प्रस्तावित संशोधन के बारे में कोई आक्षेप/सुझाव हों वह इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने से 30 दिनों के भीतर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 को भेज सकेगा।

ऐसे विनिर्दिष्ट समय में प्राप्त हुए आक्षेप/सुझावों पर सरकार संशोधन को अन्तिम रूप देने से पहले सम्यक् रूप से विचार करेगी।

आदेश द्वारा,

ए० एन० बिद्यार्थी,
वितायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F (11) 2/93, dated the 7th September, 1993, as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th September, 1993

No EXN-F (11) 2/93.—The President of India in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 1985 (Act No. 11 of 1985) proposes to amend the existing rates of entry tax, specified in column (3) of Schedule I of the aforesaid Act, in respect of goods specified in column (2) and at serial No. 5 and 7 from "3 per cent" to "4.5 per cent".

Any interested person who has any objection (s)/suggestion (s) to the proposed amendments may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-3, within a period of 30 days from the publication of the proposed amendments in the Rajpatra, Himachal Pradesh. The objections/suggestions so received within the specified period shall be duly considered by the Government before the finalisation of the draft amendments.

By order.

A. N. VIDYARATHI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.